गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 120
दि. 30.08.2025,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

प्रधानमंत्री ने भारत-जापान आर्थिक फोरम में भाग लिया

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री श्री शिगेरु इशिबा ने 29 अगस्त 2025 को टोक्यो में भारतीय उद्योग परिसंघ और कीदानरेन [जापान व्यापार महासंघ] द्वारा आयोजित भारत-जापान आर्थिक फोरम में भाग लिया। भारत-जापान बिजनेस लीडर्स फोरम के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों सहित भारत और जापान के उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियों ने बैठक में भाग लिया।

अपने संबोधन में, प्रधानमंत्री ने भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी, विशेष रूप से निवेश, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग की सफलता पर प्रकाश डाला। जापानी कंपनियों को भारत में अपनी उपस्थिति और भी अधिक बढ़ाने के लिए आमंत्रित करते हुए, उन्होंने कहा कि भारतीय विकास की गाथा उनके लिए उत्कृष्ट अवसर प्रस्तुत करती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान अशांत वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के संदर्भ में विश्वसनीय मित्रों के बीच गहरी होती आर्थिक साझेदारी विशेष रूप से प्रासंगिक है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत पूर्वानुमान, सुधारों को लेकर प्रतिबद्धता और कारोबारी सुगमता के प्रयासों ने भारतीय बाजार में निवेशकों को एक नया विश्वास कायम किया है, जो वैश्विक एजेंसियों द्वारा भारत की नवीनतम क्रेडिट रेटिंग में सुधार से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

भारत और जापान के बीच अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों, विनिर्माण, निवेश और मानव संसाधन सम्बंधी आदान-प्रदान में सहयोग की महत्वपूर्ण क्षमता के बारे में बताते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विकास में लगभग 18 प्रतिशत योगदान दे रहा है और कुछ वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच परस्पर सहयोग को देखते हुए, उन्होंने मेक इन इंडिया और अन्य पहलों की दिशा में जापान और भारत के बीच और भी अधिक व्यापारिक सहयोग के लिए पांच प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डाला। वे क्षेत्र हैं: बैटरी, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, जहाज निर्माण और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विनिर्माण;] एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, अंतरिक्ष और जैव प्रौद्योगिकी सहित प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग;] हरित ऊर्जा परिवर्तन;अगली पीढ़ी का इन्फ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आवागमन, हाई स्पीड रेल और लॉजिस्टिक शामिल हैं; और कौशल विकास और जन-जन

प्रधानमंत्री श्री इशिबा ने अपने संबोधन में, सशक्त आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण हेतु भारतीय प्रतिभाओं और जापानी प्रौद्योगिकी के बीच साझेदारी बनाने में जापानी कंपनियों की रुचि का जिक्र किया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में खेड़ा जिले के गळतेश्वर में आयोजित होगा '76वां वन महोत्सव'

(जीएनएस)।

गांधीनगर, 29अगस्त : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ह्यएक पेड़ मां के नामह्न अभियान को और अधिक सफल बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। इस अभियान को गति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में 30 अगस्त, 2025 को खेड़ा जिले की गळतेश्वर तहसील के सरनाल गांव में स्थित गळतेश्वर महादेव मंदिर के पास ह्य76 वां राज्य स्तरीय वन महोत्सवह्न मनाया जाएगा। इस अवसर पर वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री मुळुभाई बेरा और राज्य मंत्री श्री मुकेश भाई पटेल विशेष रूप से मौजूद रहेंगे।

वन एवं पर्यावरण विभाग की विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री सहित महानुभावों की उपस्थिति में शनिवार सुबह 10 बजे पांच हेक्टेयर क्षेत्र में बने 24वें सांस्कृतिक वन ह्यगळतेश्वर वनह्न का लोकार्पण समारोह आयोजित होगा। इस अवसर पर महानुभावों के करकमलों से लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के लाभ और प्रशस्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। महीसागर नदी के किनारे बना यह वन 300 से अधिक प्रजातियों के रोपण के साथ इस क्षेत्र को जैव विविधता से समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

गळतेश्वर वन के मुख्य आकर्षण

मध्य गुजरात में तैयार राज्य के 24वें सांस्कृतिक वन ह्यगळतेश्वर वनह्न में नवीन दृष्टिकोण के साथ आकर्षक मुख्य द्वार, प्रवेश परिसर, बिलि पत्र वन, शिवलिंग वन, शिव मूर्ति, गजेबो, बटरफ्लाई गार्डन, बाल क्रीड़ांगन, मातृ वन, चरोतर क्षेत्र की हस्तियों के सम्मान में बना चरोतर संकुल, गळतेश्वर डायरोमा, वॉच टावर, दुर्लभ प्रजाति के पौधों वाला नंदी वन, बाम्बू मिस्ट टनल, प्राकृतिक शिक्षण स्थल, मेज गार्डन, चेक डैम, सारस पक्षी का शिल्प, आरोग्य वन, चरक वन-प्रतिमा,

पीपल, बेल, आंवला, बरगद और अशोक सहित पांच वृक्षों वाला पंचवटी वन, ग्रह मार्ग या सूर्य मार्ग पर एक निश्चित दूरी में स्थित एक या अधिक तारों के समूहों को 27 भागों में विभाजित कर विभिन्न नक्षत्रों के नाम पर बनाए गए नक्षत्र वन के साथ ही एक राशि वन भी तैयार किया गया है, जिसमें 12 राशियों (पौराणिक शास्त्रों में नभोमंडल (आकाश) को 12 राशियों के आधार पर विभाजित किया गया है) से संबंधित विशेष पेड़ लगाए गए हैं। इसके अलावा, नवग्रह वन, फोटो पॉइंट, दीमक का ऊर्ध्वाधर टीला, मुधमक्खी का जीवनचक्र दर्शाने वाला फोटो पॉइंट, क्रॉसिंग ब्रिज-रेलिंग और सुविधा युक्त कैंटीन भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा।

इतना ही नहीं, गळतेश्वर महादेव के समीप से बहने वाली मही नदी बारहमासी नदी है, इसलिए यह पूरा क्षेत्र हरा-भरा रहता है। पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण इस वन के तैयार होने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और रोजगार के अवसरों का सृजन भी होगा, इससे इस क्षेत्र में नागरिकों के जीवन स्तर में और सुधार होगा।

गळतेश्वर का धार्मिक और पौराणिक महत्व

गुजरात के पौराणिक और ऐतिहासिक पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों में खेड़ा जिले की ठासरा तहसील के गळतेश्वर का भी विशेष महत्व है। यह स्थान सरनाल गांव के पास महीसागर और गळती नदी के संगम स्थान पर स्थित है। गळती नदी के नाम पर इसका नाम गळतेश्वर पड़ा है। सुप्रसिद्ध डाकोर के ठाकोरजी के धाम से केवल 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गळतेश्वर महादेव मंदिर में हर साल लगभग 25 लाख से अधिक श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने गळतेश्वर मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है।

महीसागर नदी के तट पर स्थित गळतेश्वर महादेव के दर्शन तथा महीसागर नदी में स्नान करने के लिए प्रतिदिन लगभग 700 से 1200 दर्शनार्थी आते हैं। शिवरात्रि के दिन यहां भव्य मेला भी लगता है।

वन महोत्सव का इतिहास

जब पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर कोई विशेष जागरूकता नहीं थी, उस समय तत्कालीन केंद्रीय कृषि एवं खाद्य मंत्री तथा गुजरात के लोकप्रिय लेखक दिवंगत श्री कन्हैयालाल मुंशी ने आज से लगभग 76 वर्ष पहले राज्य के आणंद शहर में पहली बार वन महोत्सव मनाने की शुरूआत की थी। प्रकृति संरक्षण के इस महा-उत्सव को इस वर्ष 76 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं।

भारत की विविध संस्कृतियों, परंपराओं और क्षेत्र की विशेषताओं को ध्यान में रखकर विशिष्ट वृक्षों के साथ तैयार किए गए वन को सांस्कृतिक वन कहा जाता है। पर्यावरण और संस्कृति के अनोखे समन्वय के माध्यम से वन महोत्सव कार्यक्रम को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2004 में सांस्कृतिक वनों के निर्माण की शुरूआत हुई।

वन महोत्सव के अंतर्गत राज्य में पहली बार गांधीनगर में ग्रह, नक्षत्र, राशि और संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक वन- ह्यपुनीत वनह्न बनाया गया। इस पहल के बाद हर साल राज्य के विभिन्न जिलों में सांस्कृतिक वनों को बनाने की एक शृंखला शुरू की गई। इसके तहत अब तक राज्य में विभिन्न स्थानों पर 23 सांस्कृतिक वनों का निर्माण किया गया है। ये सांस्कृतिक वन आज पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित हो गए हैं। इस वर्ष 76वें वन महोत्सव के अवसर पर एक और सांस्कृतिक वन ह्यगळतेश्वर वनह्न का लोकार्पण किया जाएगा।

केन्द्रीय मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने नई दिल्ली में ब्रिक्स सीसीआई हेल्थकेयर शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता की

(जीएनएस)।

केन्द्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री, श्री प्रतापराव जाधव ने आज नई दिल्ली में 'परम्परागत प्रथाओं और नवाचार को जोड़ना' विषय पर आयोजित ब्रिक्स सीसीआई हेल्थकेयर शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता की।

गणेश उत्सव की शुभकामनाएं देते हुए, मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया की लगभग आधी आबादी, वैश्विक जीडीपी के एक-तिहाई और विश्व व्यापार के पांचवें हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रिक्स को समावेशी और स्थायी विकास में तेजी लाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।

राज्य मंत्री श्री जाधव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अनुसंधान, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, औषधि उत्पादन और मजबूत नियामक तंत्र पर केन्द्रित एक व्यापक आयुष इकोसिस्टम विकसित किया है। आज भारत में 1,000 से ज्यादा आयुष कॉलेज हैं, जिनमें 500 से ज्यादा आयुर्वेद संस्थान शामिल हैं, जिन्हें एक व्यापक अनुसंधान नेटवर्क का सहयोग प्राप्त है।

मंत्री ने आयुष प्रणालियों की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति का उल्लेख किया - जिसमें ब्राजील में आयुर्वेदिक चिकित्सकों के समुदाय से लेकर रूस के स्वास्थ्य देखभाल ढांचे में आयुर्वेद का समावेश और चीन में पारंपरिक चिकित्सा की समानांतर उन्नति शामिल है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आयुर्वेद और योग का वैश्विक बाजार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन समावेशी, नैतिक और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करना जरूरी है। उन्होंने सार्वजनिक-निजी भागीदारी, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार, न्यूट्रास्युटिकल अनुसंधान और उद्यमियों, नवप्रवर्तकों और किसानों को मान्यता देने पर ज्यादा ध्यान देने का आह्वान किया।

भारतीय वायु सेना ने उत्तरी पंजाब और जम्मू में बाढ़ के दौरान राहत एवं बचाव अभियान तेज किया

भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने 27 अगस्त, 2025 से उत्तरी भारत में बाढ़ के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों को तेज कर दिया है और गंभीर रूप से प्रभावित जम्मू तथा पंजाब जैसे क्षेत्रों में अपने अभियान को आगे बढ़ाते ध्यान केंद्रित किया है।

चल रहे हवाई अभियान

एमआई 17 और चिनूक हेलीकॉप्टरों ने डेरा बाबा नानक, पठानकोट व अखनूर सेक्टरों में जलमग्न क्षेत्रों से भारतीय सेना तथा सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों सहित फंसे हुए नागरिकों को निकालने के लिए 55 से अधिक उड़ानें संचालित की हैं।

लोक सभा अध्यक्ष ने विधि निमार्ताओं से राष्ट्रहित के मुद्दों पर दलगत भावना से ऊपर उठकर कार्य करने का आग्रह किया

(जीएनएस)।

लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला ने आज विधिनिमार्ताओं से राष्ट्रहित के मुद्दों पर दलगत भावना से ऊपर उठकर कार्य करने का आग्रह किया । उन्होंने विधानमंडलों की बैठकों की संख्या में कमी और विधायी निकायों में सदस्यों के अमर्यादित आचरण पर क्षोभ व्यक्त किया। भुवनेश्वर, ओडिशा में संसद और राज्य विधानमंडलों की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समितियों के सभापतियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री बिरला ने कहा कि विधानमंडलों में चर्चा-संवाद का स्तर कम होना चिंता का विषय है ।

श्री बिरला ने संविधान के कालातीत मूल्यों के बारे में बात करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय और अवसर की समानता न केवल हमारे संविधान की विशेषता है, बल्कि पिछले 75 वर्षों से भारत की लोकतांत्रिक यात्रा का मार्गदर्शन भी कर रही है ।

डॉ. बी.आर. अंबेडकर के विचारों का उल्लेख करते हुए श्री बिरला ने कहा कि वह एक ऐसे भारत की कल्पना करते थे जहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और वंचित वर्ग

मयार्दा, सम्मान और समान अवसरों के साथ रह सकें। श्री बिरला ने आगे कहा कि दशकों में इस विजन को ठोस रूप दिया गया है, जिससे इन समुदायों के सदस्य भारत के राष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों तक देश के सर्वोच्च पदों पर आसीन हैं जिससे भारत के लोकतन्त्र की परिपक्वता और समावेशिता का परिचय मिलता है ।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समितियों के सभापतियों का पहला सम्मेलन 1976 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसके बाद, 1979, 1983, 1987 और 2001 में सम्मेलन आयोजित किए गए, जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और संवैधानिक सुरक्षोपायों के विभिन्न आयामों पर गहन चर्चा की गई । इस सम्मेलन का आयोजन दिल्ली से बाहर पहली बार किया जा रहा है।

श्री बिरला ने कल्याणकारी योजनाओं को समाज के वंचित वर्गों तक सही मायने में पहुँचाने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए सरकारी धन के प्रभावी उपयोग और सुदृढ़ निगरानी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया और समावेशी विकास को गति देने में वित्तीय अनुशासन और प्रशासनिक जवाबदेही की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य वंचित वर्गों के उत्थान के उद्देश्य से सामाजिक कल्याण पहलों के लिए हर साल पर्याप्त संसाधन आवंटित किए जाते हैं । इसके साथ ही उन्होंने विकास के लाभ का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए समय पर कार्यान्वयन और नियमित निगरानी के महत्व को भी रेखांकित किया। इस बात पर जोर देते हुए कि सच्चा सशक्तिकरण वित्तीय सहायता से बढ़कर आत्मनिर्भरता, सम्मान और विकास के अवसरों को बढ़ावा देना है

राष्ट्रपति ने स्कोप उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए

भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में सीपीएसई महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे: राष्ट्रपति मुर्मु

(जीएनएस)।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज (29 अगस्त, 2025) नई दिल्ली में वर्ष 2022-23 के लिए स्कोप उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए।

इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि स्कोप उत्कृष्टता पुरस्कार देश के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव हैं। सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, तकनीकी और नैतिक - सभी मानदंडों पर अच्छा प्रदर्शन एक अच्छे उद्यम की पहचान है। उन्होंने सतत विकास, कॉर्पोरेट प्रशासन, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और नवाचार जैसे कई आयामों में अच्छे प्रदर्शन को सम्मानित करने के लिए स्कोप की सराहना की। राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि यह प्रगति और विकास के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण को दर्शाता है।

राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र आर्थिक विकास और सामाजिक समावेशन का एक शक्तिशाली माध्यम रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने औद्योगीकरण, अवसंरचना विकास, सामाजिक उत्थान और संतुलित क्षेत्रीय विकास की नींव रखी है। समय के साथ इन उपक्रमों ने स्वयं को विकसित किया और बदला है। सरकार और समाज की इनसे अपेक्षाएं भी बदली हैं। राष्ट्रपति ने प्रसन्नता व्यक्त की कि इन सभी परिवर्तनों के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने प्रदर्शन के जरिए से आर्थिक और राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि आर्थिक और वित्तीय योगदान के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने संतुलित और समावेशी विकास को भी प्राथमिकता दी है तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों को सर्वोपरि रखा है। उनके योगदान और भूमिका को देखते हुए यह कहना उपयुक्त है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम देश और जनता के लिए विकास के उत्प्रेरक तथा समृद्धि के स्तंभ हैं। उन्होंने कहा कि इन उद्यमों ने प्रशासन और पारदर्शिता के कई अच्छे उदाहरण और मॉडल भी प्रस्तुत किए हैं।

राष्ट्रपति को यह जानकर खुशी हुई कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) आत्मनिर्भर भारत और 'मेक इन इंडिया' जैसे राष्ट्रीय अभियानों में प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी वायु रक्षा नियंत्रण एवं रिपोर्टिंग प्रणाली - आकाशतीर ने अपनी अचूक क्षमता का प्रदर्शन किया।

सम्पादकीय

धीमी हुई हीरे की चमक

भारत पर अतिरिक्त 25 फीसदी अमेरिकी टैरिफ बुधवार को लागू हो गया। इसी के साथ भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त टैरिफ बढ़कर 50 फीसद हो गया। माना जा रहा है 48 अरब डॉलर से ज्यादा का अमेरिका को दिए जाने वाला भारतीय निर्यात इससे प्रभावित होगा। भारत के वस्त्र, परिधान, रत्न आभूषण, झींगा, चमड़ा, टेक्सटाइल इत्यादि बहुत से उद्योगों पर सीधा असर पड़ेगा। मैंने वुछ दिन पहले हरियाणा के उद्योगों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का वर्णन किया था। आज मैं गुजरात के सूरत हीरा उद्योग के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। सूरत दुनिया में हीरा की कटिंग और पालिशिंग के लिए जाना जाता है। लेकिन अब इस उद्योग पर निर्भर रहने वाले लोग मुश्किल में हैं। 50 फीसदी टैरिफ ने इस क्षेत्र के व्यापारियों के साथ-साथ मजदूरों को भी चिंता में डाल दिया है। हीरा उद्योग से जुड़े 25 लाख से ज्यादा कामगार इससे प्रभावित हो सकते हैं। 50 फीसदी टैरिफ लगाने का असर सबसे ज्यादा इस क्षेत्र पर पड़ रहा है क्योंकि सूरत का हीरा उद्योग अमेरिका के किए जाने वाले निर्यात पर ज्यादा निर्भर है। वुछ लोगों का मानना है कि अगर टैरिफ कम नहीं किया गया तो कई व्यापारी हीरा उद्योग से बाहर हो जाएंगे। कई लोगों की नौकरियां चली जाएंगी और भयंकर मंदी आ जाएगी। हालांकि दूसरी ओर हीरा उद्योग से जुड़े संगठन जैसे सूरत डायमंड एसोसिएशन और साउथ गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स का मानना है कि अमेरिकी टैरिफ से वुछ मंदी आएगी लेकिन समय के साथ स्थिति स्थिर हो जाएगी क्योंकि भारत को हीरा उद्योग की जितनी जरूरत है, अमेरिका में भी हीरों की उतनी ही मांग है। इसलिए वहां के लोग, व्यापारी भी इस समस्या का समाधान चाहते हैं। सूरत की कई छोटी पैक्ट्रियों में 20 से 200 श्रमिक तक काम करते हैं। राज्यों में तो यह संख्या 500 तक होती है और सूरत में ऐसी हजारों पैक्ट्रियां हैं। हाल ही में कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। सूरत में कई छोटी-बड़ी पैक्ट्रियों का यह हाल है कि 20 साल पहले शैलेश मंगुकिया ने सिर्प एक पॉलिशिंग व्हील (चक्की) से हीरा पालिश करने की एक यूनिट शुरू की थी जो अब इतनी बड़ी हो गई कि यहां कामगारों की संख्या 3 से बढ़कर 300 हो गई, हालांकि अब इस पैक्ट्री में सिर्प 70 लोग ही बचे हैं। वे कहते हैं कि सारे आर्डर वैंसल कर दिए गए है। मजदूरों को कहना पड़ रहा है कि काम नहीं है। आर्डर नहीं होने की वजह से काम नहीं है और काम न होने की वजह से सैलरी देने के पैसे नहीं हैं। पिछले साल अगस्त में उनकी पैक्ट्री में हर महीने औसतन 2000 हीरों की प्रोसेसिंग हो रही थी। लेकिन इस साल घटकर मात्र 300 रह गई है। श्रमिक सुरेश राठौर ने कहा, आमतौर पर हमें जन्माष्टमी के दौरान सिर्प 2 दिन की छुट्टी मिलती थी, इस बार हमें 10 दिन की बिना वेतन छुट्टी दी गई। हम ऐसे वैसे रह सकते हैं? सुरेश राठौर जैसे कई कारीगर हैं, जो इस तरह प्रभावित हो रहे हैं। सूरत डायमंड पालिशर्स यूनियन के भावेश टांक कहते हैं कि हमारे पास इस समय बहुत से जौहरी शिकायत लेकर आ रहे हैं कि उनका वेतन कम कर दिया गया या उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। हजारों मजदूरों की आमदनी कम हो रही है। उद्योग जगत के नेताओं ने एक स्पेशल डायमंड टास्क फोर्स बनाई है। जो इस स्थिति का समाधान निकालने की कोशिश करेगी। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने इस बारे में बीबीसी से कहा, अमेरिकी बाजार पर भारी निर्भरता के कारण लंबे समय में बड़ा झटका लगेगा। पुराने आर्डर पूरे हो गए हैं, लेकिन नए आर्डर का भविष्य अस्पष्ट है। सरकार को तुरंत मदद करनी होगी। उन्होंने कहा कि कई व्यापारी मध्य पूर्व और यूरोप जैसे बाजारों में अवसर तलाश रहे हैं और वुछ तो बाईपास मार्गो के जरिए अमेरिका तक माल पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि उनके अनुसार अब अलग- अलग यूरोपीय देशों में नए बाजारों की तलाश करने की जरूरत है। सवाल यह है कि सूरत के हीरा उद्योग को वैसे बचाया जा सकता है? इस उद्योग जगत के वुछ लोगों का कहना है कि आने वाले दिनों में स्थिति और खराब हो सकती है। जेम एंड ज्वैलरी एक्सपर्ट प्रमोशन काउंसिल (जीजेईपीसी) के गुजरात अध्यक्ष जयंति भाई सावलिया का मानना है कि अब समय आ गया है कि अमेरिका पर निर्भरता कम की जाए और अन्य बाजारों की ओर देखा जाए।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खेल महाकुंभ-2025 के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरूआत की

गांधीनगर, 29अगस्त : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की जयंती पर देश भर में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर शुक्रवार को गुजरात के सबसे बड़े खेल उत्सव 'खेल महाकुंभ-2025' के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रारंभ किया।

राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ गुजरात की ओर से अहमदाबाद के कर्णावती क्लब में अवॉर्ड समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर खेल क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करने वाले खेल जगत से जुड़े 20 लोगों को अवॉर्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस अवसर पर कहा कि खेल भावना किसी भी खेल का एक अनिवार्य पहलू है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ गुजरात की ओर से खेल क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले महानुभावों को सम्मानित करने का कार्यक्रम हम सभी के लिए गर्व की बात है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेल दिवस इस वर्ष गुजरात के लिए काफी अहम है, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने कॉमनवेल्थ खेल 2030 के लिए अहमदाबाद की दावेदारी को मंजूरी दी है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि विश्वस्तरीय स्टेडियम, अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं और उत्साही खेल संस्कृति वाला अहमदाबाद इस खेल के आयोजन के लिए एक आदर्श मेजबान शहर होगा।

गुजरात में खेल संस्कृति के संबंध में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि गुजरात को ढाई दशकों से खेल और फिटनेस को लेकर प्रधानमंत्री के विजन का लाभ मिल रहा है। आज गुजरात में जिस पैमाने पर खेल संस्कृति विकसित हुई है, यह उनके ही विजन का ही परिणाम है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'खेले वह खिले' मंत्र के साथ वर्ष 2010 में गुजरात में खेल महाकुंभ की शुरूआत की थी। खेल महाकुंभ 3.0 में रिकॉर्ड ब्रेक 71 लाख से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। उन्होंने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर शुरू हुए खेल महाकुंभ-2025 के रजिस्ट्रेशन

का उल्लेख करते हुए राज्य के सभी खेल प्रेमियों से इसमें रजिस्ट्रेशन कराने का अनुरोध किया।

राज्य में खेलों के बुनियादी ढांचे और खेल संस्कृति के विकास के बारे में आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन के परिणामस्वरूप गुजरात ने खेल क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। आज उभरते खिलाड़ियों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, उपकरण और सुविधाएं तथा प्रशिक्षण आसानी से उपलब्ध हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में पिछले दो दशक में राज्य में खेलों के बुनियादी ढांचे का निरंतर विकास हुआ है। 2002 में राज्य में 3 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स थे, जबकि आज राज्य के खिलाड़ियों के लिए 24 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उपलब्ध हैं।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अहमदाबाद के नारणपुरा इलाके में 22 एकड़ क्षेत्र में मल्टी यूटिलिटी स्पोर्ट्स सेंटर आकार ले रहा है। यही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेन्द्र मोदी स्टेडियम के पास 233 एकड़ क्षेत्र में सरदार वल्लभभाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव का निर्माण हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गत एक दशक में देश की खेल संस्कृति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद सत्र के दौरान राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित कर खिलाड़ियों के हितों की रक्षा का ऐतिहासिक कदम उठाया है। भारत को वैश्विक खेल जगत का पावर हाऊस बनाने और 2036 के ओलंपिक खेलों सहित अंतरराष्ट्रीय खेल कार्यक्रमों में मजबूत दावेदारी करने के उद्देश्य से स्पोर्ट्स पॉलिसी-2025 भी घोषित की गई है।

मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से देश में ही बने स्वदेशी उत्पाद और खेल सामग्री खरीदकर वोकल फॉर लोकल के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत और विकसित गुजरात से विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का अनुरोध किया।

राज्य सभा सांसद श्री नरहरिभाई अमीन ने कहा कि आज भारत खेल क्षेत्र में नए मील के पत्थर स्थापित कर रहा है, इसमें गुजरात का भी बड़ा योगदान रहा है। राज्य में खेल गतिविधियों का दायरा बहुत ही प्रशंसनीय तरीके से बढ़ रहा है। इन गतिविधियों को जन-जन तक पहुंचाने वाले स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ गुजरात का योगदान भी अहम है। उन्होंने कहा कि देश में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की शुरूआत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने की है।

पद्मश्री और कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता मीराबाई चानू ने कहा कि गुजरात खेल प्रिय राज्य है। उन्होंने कहा कि कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में उन्हें उपलब्धि हासिल हुई है, वह भी गुजरात में। यह उनके लिए बहुत ही गौरव की बात है। उन्होंने खिलाड़ियों से अपील करते हुए कहा कि अपने खेल में सर्वश्रेष्ठ देने का संकल्प ही हमारी ताकत है।

80% राष्ट्रीय योगदान और ₹3,995 करोड़ निर्यात के साथ जीरा व्यापार में उंझा का परचम, वीजीआरसी में होगी विशेष चर्चा

ऊंझा से ₹3,995 करोड़ जीरा और मसाला बीजों का निर्यात
पिछले वर्ष की तुलना में उंझा में जीरे की आवक में 17.5% की वृद्धि
गुजरात से जीरा व मसाला बीजों का 101 देशों को निर्यात; प्रमुख बाजार चीन, बांग्लादेश, वअए, अमेरिका व मोरक्को

गांधीनगर, 29 अगस्त 2025: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के सक्षम नेतृत्व में गुजरात का कृषि क्षेत्र निरंतर नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। आधुनिक कृषि तकनीकों का अपनाना, सुदृढ़ बाजार ढांचा और वैश्विक व्यापार में सक्रिय भागीदारी ने राज्य को न केवल राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी एक मजबूत पहचान दिलाई है।

इसी प्रगति का उत्कृष्ट उदाहरण है उत्तर गुजरात के मेहसाणा जिले का ऊंझा, जिसने अपनी विशिष्ट पहचान के साथ देश-विदेश के मसाला बाजार में एक मजबूत स्थान बनाया है। भारत ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी उच्च गुणवत्ता वाला जीरा और अन्य मसाला बीजों की निरंतर आपूर्ति करते हुए ऊँझा ने गुजरात की नेतृत्वकारी स्थिति को और सुदृढ़ किया है।

आज, जीरा और अन्य मसाला बीजों के निर्यात में गुजरात का योगदान देश की कुल हिस्सेदारी का लगभग 80% है, जो राज्य के कृषि क्षेत्र की असाधारण सफलता का प्रमाण है। वित्त वर्ष 2024-25 के आँकड़े बताते हैं कि केवल मेहसाणा जिले से ही लगभग ₹3,995 करोड़ मूल्य के जीरा और अन्य मसाला बीज 101 देशों को निर्यात किए गए। इनमें प्रमुख बाजार चीन (25%), बांग्लादेश (16%), संयुक्त अरब अमीरात (10%), अमेरिका (5%) और मोरक्को (4%) शामिल हैं।

कृषि मंत्रालय के एगमार्कनेट के ताजा आंकड़ों के अनुसार, 15 फरवरी से 10 अप्रैल 2025 के बीच उंझा एपीएमसी में 54,410 मीट्रिक टन (एमटी) जीरे की आवक दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष की 46,313 एमटी की तुलना में 17.5% अधिक है। यह वृद्धि न केवल किसानों की मेहनत का परिणाम है, बल्कि उंझा की मजबूत आपूर्ति श्रृंखला का प्रमाण भी है, जिसने इसे मसाला अर्थव्यवस्था का धड़कता हुआ केंद्र बनाए रखा है। यह नेटवर्क हजारों किसानों और व्यापारियों को रोजगार व व्यापारिक अवसर प्रदान करता है। वर्ष 2023-24 के आधिकारिक पूवार्नुमान के मुताबिक, इस क्षेत्र में कुल 72,100.59 एमटी जीरे का उत्पादन हुआ, जिसमें बनासकांठा 41,800.73 एमटी के साथ पहले और पाटन 29,900.09 एमटी के साथ दूसरे स्थान पर रहा।

दफन सोना, घातक झूठः कलर्स का 'नयनतारा' सामने लाता है परिवार के भीतर छिपे कातिल को

खजाने की खोज पूरी हो चुकी है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है। कलर्स के शो नयनतारा में जीत का जश्न मनाने का जो पल होना चाहिए था, वही परिवार के लिए सबसे विनाशकारी सच लेकर आता है। नयनतारा (श्रुति बिष्ट द्वारा निभाया किरदार), जिसे परलोक से आवाजें सुनने की अलौकिक शक्ति प्राप्त है, हमेशा इस वरदान का इस्तेमाल लोगों की रक्षा और भलाई के लिए करती आई है। लेकिन लता (नारायणी शास्त्री), जिस पर पूरा परिवार एक आदर्श माँ के रूप में भरोसा करता है—वह नयनतारा की शक्ति का इस्तेमाल अपने खतरनाक खेल के लिए करती रही।

शुरूआत से ही लता का एकमात्र जुनून था—परिवार का खोया हुआ खजाना। उसने नयनतारा की अलौकिक शक्ति को अपनी महत्वाकांक्षा पूरा करने का साधन बना लिया। सुरजो (अर्जुन चक्रवर्ती), जो नयनतारा का पति है, उसकी जान को दांव पर लगाकर लता ने नयनतारा को खजाने की खोज में मजबूर किया।

विषैले सांपों और अनगिनत मुश्किलों से लड़ते हुए नयनतारा असंभव को संभव कर दिखाती है और लता को वह सब मिल जाता है जिसकी उसे चाह थी। लेकिन लता को अंदाजा नहीं था कि यही खजाना उसकी बबार्दी का कारण बनेगा, क्योंकि नयनतारा के पास ऐसा दांव था जिसके बारे में लता को कुछ पता ही नहीं था। नयनतारा जानती थी कि ठोस सबूत के बिना कोई भी लता की चालबाजी पर यकीन नहीं करेगा। और सबूत क्या हो सकता था, सिवाय उसी दफन खजाने के, जिसे पूरा परिवार देख सकता था? सबके सामने नयनतारा लता से पूछती है कि उसे क्या दिखाई दे रहा है। यहीं उसका झूठ खुल जाता है, क्योंकि जहाँ सबको सोने के गहने दिखाई देते हैं, वहीं लता को सिर्फ. रेंगते हुए सांप दिखाई देते हैं।

न्याय के उस पल में नयनतारा वह सच उजागर करती है जिसे लता ने सालों से छुपा रखा था। सुरजो की प्यार करने वाली माँ का मुखौटा उतर जाता है और सामने आती है एक कातिल की असली सूरत। परिवार विश्वासघात के इस झटके से हिलकर रह जाता है। सुरजो, जो कभी नयनतारा पर शक करता था, अब उसी से वादा करता है कि वह उसे वह सम्मान और स्थान देगा जिसकी वह हकदार है—उससे दोबारा विवाह करके।

खजाना मिल गया, झूठ का भंडाफोड़ हो गया और प्यार की जीत होती दिखी। लेकिन नयनतारा की दुनिया में कुछ राज कभी चैन से नहीं सोते। अतीत की एक परछाईं फिर लौटने वाली है, और यह होगा अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट। क्या नयनतारा इस नए तूफान का सामना कर पाएगी?

देखिए 'नयनतारा' रोजाना रात 8:30 बजे, सिर्फ. कलर्स पर

भारतीय महासागर नौसेना संगोष्ठी (आईओएनएस-2025) के तत्वावधान में आयोजित 'उभरते हुए नेताओं की पैनल चर्चा' का समापन

(जीएनएस)।

हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (आईओएनएस) के तत्वावधान में 'उभरते हुए नेता पैनल चर्चा' 27 से 28 अगस्त 2025 तक दक्षिणी नौसेना कमान, कोच्चि में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में 19 सदस्य देशों के प्रतिनिधि एक मंच पर आए, जिससे युवा नौसेना के नेताओं को विचारों का आदान-प्रदान करने, अनुभव साझा करने और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग के भविष्य पर विचार-विमर्श करने के लिए एक समावेशी मंच मिला।

दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, वाइस एडमिरल वी. श्रीनिवास ने मुख्य भाषण देते हुए विचारोत्तेजक चचाओं का मंच तैयार किया। उनके संबोधन ने हिंद महासागर क्षेत्र में संवाद, आपसी विश्वास और सहयोगात्मक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

दो दिवसीय कार्यक्रम में चार विषयगत सत्र शामिल थे। उद्घाटन सत्र में हिंद महासागर क्षेत्र के सामरिक

महत्व और युवा अधिकारियों के दृष्टिकोण से सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की गई। इसमें हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा, समुद्री व्यापार सुरक्षा, जलवायु प्रभाव और भू-राजनीतिक गतिशीलता से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला गया और साथ ही इन चुनौतियों से निपटने के तरीकों पर युवा अधिकारियों के नवोन्मेषी दृष्टिकोणों को भी शामिल किया गया।

दूसरा सत्र 'समुद्री सुरक्षा में उभरती प्रौद्योगिकियों' पर केंद्रित था, जिसमें प्रतिभागियों ने समुद्री सुरक्षा के समर्थन में समुद्री टोही, एआई-सक्षम प्रणालियों, मानवरहित प्लेटफार्मों, साइबर खतरों और अंतरिक्ष-आधारित निगरानी में उभरती प्रौद्योगिकियों का पता लगाया।

दूसरे दिन की शुरूआत 'समुद्री सुरक्षा की दिशा में सहयोग को बढ़ावा देने में आईओएनएस की भावी भूमिका' विषय पर तीसरे सत्र से हुई। पैनलिस्टों ने क्षेत्रीय साझेदारियों को मजबूत करने के लिए बेहतर अंतर-संचालन, संयुक्त अभ्यास और पेशेवर आदान-प्रदान की आवश्यकता पर जोर दिया। अंतिम सत्र में 'आईओएनएस देशों के बीच प्रशिक्षण क्षमताओं का दोहन - भविष्य की रूपरेखा' पर चर्चा हुई। चचाएँ संसाधनों के एकत्रीकरण, प्रशिक्षण संबंधों के विस्तार और सामूहिक तैयारी को बढ़ाने के लिए साझा ढाँचे के विकास पर केंद्रित रहीं।

पैनल चचाओं के अलावा, सांस्कृतिक और सामाजिक संवाद भी आयोजित किए गए, जिससे प्रतिभागियों को केरल की समुद्री विरासत का अनुभव करने और व्यक्तिगत सौहार्द बढ़ाने का अवसर मिला। पेशेवर संवाद और अनौपचारिक मेल-मिलाप के मिश्रण ने विचारों के समग्र आदान-प्रदान को समृद्ध बनाया।

डाक विभाग ने भारत के डिजिटल पता प्रणाली को उन्नत बनाने के लिए मैपमाईइंडिया के साथ साझेदारी की

(जीएनएस)।

संचार मंत्रालय के डाक विभाग (डीओपी) ने अवस्थिति प्रौद्योगिकी, आईओटी और भू-स्थानिक समाधान प्रदान करने वाली कंपनी, मैपमाईइंडिया-मैपल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोग का उद्देश्य डिजिपिन के विकास और कार्यान्वयन में सहायता के लिए मैपमाईइंडिया के मानचित्रण प्लेटफॉर्म और उत्पादों का उपयोग करना है।

डाक भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में डाक विभाग और मैपमाईइंडिया-मैपल्स के नामित प्रतिनिधियों ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

समझौते की शर्तों के तहत, मैपमाईइंडिया "अपने डिजिपिन को जानें" अनुप्रयोग में एकीकरण के लिए आधार मानचित्र प्रदान करेगा, जिससे उपयोगकताओं के लिए दृश्यता बढ़ेगी और भौगोलिक स्थान के आधार पर सटीक डिजिपिन तैयार करना संभव होगा। इसके अलावा, मैपल्स अनुप्रयोग में डिजिपिन कार्यक्षमता को शामिल किया जाएगा, जिससे उपयोगकर्ता डिजिपिन का उपयोग करके स्थानों की खोज कर सकेंगे। मैपमाईइंडिया अपने डेटाबेस में पहले से ही पहचान किये गये पतों पर डिजिपिन के आवंटन की सुविधा भी प्रदान करेगा, जिससे अवस्थिति-आधारित सेवाओं को मजबूती मिलेगी और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर डिजिपिन को व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा मिलेगा।

इस अवसर पर, डाक विभाग के सदस्य (संचालन) श्री हरप्रीत सिंह ने कहा, "यह साझेदारी डिजिपिन की

पहुँच और सुगमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाएगी। मैपमाईइंडिया के मानचित्रण प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण करके, हम एक मानकीकृत डिजिटल पता प्रणाली बना रहे हैं जिससे लाखों नागरिकों को लाभ होगा और कुशल सेवा वितरण के लिए भारत की डिजिटल अवसंरचना को मजबूती मिलेगी।"

मैपमाईइंडिया मैपल्स के सह-संस्थापक और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री राकेश वर्मा ने कहा, "मैपमाईइंडिया मैपल्स को पूरी तरह से स्वदेशी राष्ट्रीय डिजिटल पता प्रणाली विकसित करने के लिए डाक विभाग के साथ हाथ मिलाने पर गर्व है। डाक विभाग के डिजिपिन अनुप्रयोगों में एकीकृत होने के बाद, एपीआई और एसडीके का मैपमाईइंडिया मैपल्स सूट, डिजिपिन से संबंधित विभिन्न सेवाओं और समाधानों के निर्माण द्वारा अरबों भारतीय नागरिकों और व्यवसायों को सशक्त बनाएगा, साथ ही मैपल्स ऐप के माध्यम से उन तक निर्बाध पहुँच भी सुनिश्चित करेगा।"

सरकार ने सैन्य प्रशिक्षण से मेडिकल बोर्ड-आउट अधिकारी कैडेटों के लिए ईसीएचएस सुविधाओं के लिए मंजूरी दी

(जीएनएस)।

सरकार ने सशस्त्र बलों की गरिमा और कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए उन अधिकारी कैडेटों को पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) सुविधा प्रदान करने को मंजूरी दे दी है, जो सैन्य प्रशिक्षण की वजह से या उसके कारण उत्पन्न चिकित्सा आधार पर प्रशिक्षण से वंचित (बोर्ड-आउट) रह जाते हैं। देश की सेवा करने की आकांक्षा से एनडीए, ओटीए और आईएमए जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में शामिल होने वाले कैडेट अक्सर आजीवन विकलांगता का सामना करते हैं, लेकिन वर्तमान में वे ईसीएचएस के लिए पात्र नहीं हैं क्योंकि उन्हें पूर्व सैनिक (ईएसएम) का दर्जा नहीं दिया जाता है।

यह कदम उन कैडेटों पर लागू है जिन्हें प्रशिक्षण पूरा होने से पहले ही चिकित्सा आधार पर प्रशिक्षण से वंचित कर दिया गया है। भविष्य में इसी तरह के मामलों में भी इसका विस्तार किया जा सकता है। मानवीय प्रकृति और परिवारों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने अन्य श्रेणियों के लिए कोई मिसाल कायम किए बिना ऐसे कैडेटों के लिए गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल को मंजूरी दी है। ईसीएचएस सुविधाओं की मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :

ईसीएचएस की सदस्यता के लिए आवेदन करें और ईसीएचएस नियमों को स्वीकार करें

केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए सुविधा

ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक्स से निःशुल्क ओपीडी सेवाओं का लाभ उठाएं

ईसीएचएस पैनलबद्ध अस्पतालों में कैशलेस ओपीडी/आईपीडी/जांच का लाभ उठाएं

किसी अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजना का सदस्य नहीं होना चाहिए।

ईसीएचएस योजना में शामिल होने के लिए अधिकारी कैडेटों से एकमुश्त सदस्यता शुल्क (अर्थात ईएसएम अधिकारियों के लिए वर्तमान में लागू 1.20 लाख रुपये) नहीं लिया जाएगा।

यद्यपि प्रतिवर्ष कुछ कैडेट प्रभावित होते हैं, फिर भी उनके परिवारों पर आर्थिक और भावनात्मक बोझ काफी अधिक होता है। ऐसे मामलों में, ऐसे कैडेटों को मासिक अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, विकलांगता की सीमा (20 प्रतिशत से 100 प्रतिशत) के आधार पर, ऐसे कैडेटों को मासिक अनुग्रह राशि भी प्रदान की जाती है। इस अनुमोदन के साथ, ये कैडेट अब ईसीएचएस के अंतर्गत कैशलेस और कैपलेस स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के पात्र होंगे।

ईसीएचएस की शुरूआत अप्रैल 2003 में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए सशस्त्र बलों तथा देश भर के निजी सूचीबद्ध/सरकारी अस्पतालों के विद्यमान चिकित्सा ढांचे का उपयोग करके की गई थी।

RNI No. GUJGUJ/2011/39228 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004, Ahmedabad,Gujarat-380 004. (2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset,Bhatiya Ni Wadi, Opp Railway Station, Kalupur, Ahmedabad,-380002,Ahmedabad,Gujarat-380 002 (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset,Bhatiya Ni Wadi, Opp Railway Station, Kalupur, Ahmedabad,-380002,Ahmedabad,Gujarat-380 002. and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPKLAL SHAH

उत्तर पूर्व रेलवे के गोरखपुर-गोंडा खंड एवं गोरखपुर-आनन्द नगर खंड में ब्लॉक के कारण पश्चिम रेलवे की कुछ ट्रेनें होंगी प्रभावित

मुंबई, गोरखपुर–डोमिनगढ़ स्टेशनों के बीच तृतीय लाइन कमीशनिंग कार्य तथा गोरखपुर–नकहा जंगल स्टेशनों के बीच डबलिंग कार्य हेतु उत्तर पूर्व रेलवे पर 22 सितंबर से 26 सितंबर, 2025 तक ब्लॉक लिया जाएगा। इस कारण पश्चिम रेलवे की कुछ ट्रेनें निरस्त, आंशिक रूप से निरस्त तथा परिवर्तित मार्ग से चलेंगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रभावित ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

निरस्त होने वाली ट्रेनें:

1. 26 सितंबर, 2025 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 15068 बांद्रा टर्मिनस–गोरखपुर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी।

2. 24 सितंबर, 2025 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 15067 गोरखपुर–बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस निरस्त रहेगी।

3. 28 सितंबर, 2025 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 15046 ओखा–गोरखपुर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी।

4. 25 सितंबर, 2025 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 15045 गोरखपुर–ओखा एक्सप्रेस निरस्त रहेगी।

शॉर्ट टर्मिनेट/ओरिजिनेट/आंशिक रूप से निरस्त होने वाली ट्रेनें:

1. ट्रेन संख्या 19489 अहमदाबाद–गोरखपुर एक्सप्रेस 23 से 26 सितंबर, 2025 तक वाराणसी स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी। इसलिए, यह ट्रेन वाराणसी और गोरखपुर के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।

2. ट्रेन संख्या 19490 गोरखपुर–अहमदाबाद एक्सप्रेस 24 से 27 सितंबर, 2025 तक वाराणसी स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी। इसलिए, यह ट्रेन गोरखपुर और वाराणसी के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।

3. ट्रेन संख्या 19091 बांद्रा टर्मिनस–गोरखपुर हमसफर एक्सप्रेस 22 सितंबर, 2025 को वाराणसी स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी। इसलिए, यह ट्रेन वाराणसी और गोरखपुर के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।

4. ट्रेन संख्या 19092 गोरखपुर–बांद्रा टर्मिनस हमसफर एक्सप्रेस 23

उत्तर रेलवे के कठुआ-माधोपुर पंजाब सेक्शन बारिश के कारण रेल यातायात प्रभावित

उत्तर रेलवे के कठुआ–माधोपुर पंजाब सेक्शन में डाउन लाइन पर ब्रिज संख्या 17 पर बारिश के चलते मिसअलाइमेंट होने के कारण रेल यातायात स्थगित किया गया है। जिसके कारण अहमदाबाद मण्डल से चलने/गुजरने वाली कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेगी। जिसका विवरण निम्नानुसार है:

निरस्त ट्रेनें:–

1. दिनांक 31.08.2025 की ट्रेन संख्या 19223 साबरमती–जम्मू तवी एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

2. दिनांक 31.08.2025 की ट्रेन संख्या 12478 श्री माता वैष्णो देवी कटरा– जामनगर एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

3. दिनांक 31.08.2025 की ट्रेन संख्या 19415 साबरमती–श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

4. दिनांक 31.08.2025 की ट्रेन संख्या 19224 जम्मू तवी–साबरमती एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

5. दिनांक 31.08.2025 की ट्रेन संख्या 19107 भावनगर टर्मिनस–शहीद कप्तान तुषार महाजन ऊधमपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

ट्रेनों के ठहराव, समय और संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया ६६६.ल्ल०४१८.ल्लॅल्लि१ं'.ङ्ग५.ल्ल

पश्चिम रेलवे द्वारा चार जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे विस्तारित

मुंबई,

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा विशेष तौर पर त्योहारी सीजन के दौरान उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से विशेष किराए पर 04 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरों को विस्तारित किया गया है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन ट्रेनों का विवरण इस प्रकार है:

ट्रेन संख्या 09189/09190 मुंबई सेंट्रल – कटिहार (साप्ताहिक) स्पेशल

ट्रेन संख्या 09189 मुंबई सेंट्रल – कटिहार स्पेशल को 27 दिसंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09190 कटिहार – मुंबई सेंट्रल स्पेशल को 30 दिसंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है।

ट्रेन संख्या 09049/09050 दादर – भुसावल (साप्ताहिक) स्पेशल

ट्रेन संख्या 09049 दादर – भुसावल स्पेशल को 26 दिसंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09050 भुसावल – दादर स्पेशल को 26 दिसंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है।

ट्रेन संख्या 09051/09052 दादर – भुसावल (त्रि–साप्ताहिक) स्पेशल

ट्रेन संख्या 09051 दादर–भुसावल स्पेशल को 31 दिसंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09052 भुसावल–दादर स्पेशल को 31 दिसंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है।

ट्रेन संख्या 09057/09058 उधना–मंगलूरु (द्वि–साप्ताहिक) स्पेशल

ट्रेन संख्या 09057 उधना–मंगलूरु स्पेशल को 31 दिसंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09058 मंगलूरु–उधना स्पेशल को 1 जनवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है।

ट्रेन संख्या 09189, 09049, 09051 एवं 09057 के विस्तारित फेरों की बुकिंग 1 सितम्बर, 2025 से पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

पश्चिम रेलवे पर रविवार, 31 अगस्त, 2025 को दिवसकालीन ब्लॉक नहीं

मुंबई, पश्चिम रेलवे का मुंबई सेंट्रल (मेन) स्टेशन पर 30/31 अगस्त, 2025 की मध्यरात्रि को रात्रिकालीन ब्लॉक

रेल पथ, सिगनलिंग प्रणाली तथा ऊपरी उपस्करों के रख–रखाव हेतु शनिवार/रविवार यानी 30/31 अगस्त, 2025 की मध्यरात्रि को मुंबई सेंट्रल (मेन) स्टेशन की सभी लाइनों पर 00:30 बजे से 04.00 बजे तक जम्बो ब्लॉक लिया जाएगा।

पश्चिम रेलवे के उपनगरीय खंड पर रविवार, 31 अगस्त, 2025 को कोई दिवसकालीन ब्लॉक नहीं रहेगा।

भावनगर रेलवे मंडल पर 'मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन शिविर' का आयोजन

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल में रनिंग स्टाफ एवं अन्य विभागों के सभी कर्मचारियों के लिए 'मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन शिविर' का आयोजन किया गया। यह शिविर 29 अगस्त, 2025 (शुक्रवार) को भावनगर परा स्थित कम्युनिटी हॉल में आयोजित हुआ।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार यह शिविर अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री हिमाँशु शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस आयोजन का संचालन स्थापना विभाग की वेलफेयर टीम द्वारा वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री हुबलाल जगन की अगुवाई एवं उनके दिशा–निर्देशों में कर्मचारी हित निधि (रइत्र) से किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री हिमाँशु शर्मा एवं उपस्थित अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन से किया गया। इसके उपरांत 'तनाव मुक्त जीवन' विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रम्ह कुमारी संस्थान, भावनगर के प्रतिनिधियों ने जीवन में मानसिक तनाव को दूर करने की विभिन्न विधियाँ बताईं तथा योग और प्राणायाम को जीवनशैली का हिस्सा बनाने पर बल दिया।

अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री हिमाँशु शर्मा ने अपने प्रासंगिक उद्बोधन में कर्मचारियों को सकारात्मक सोच एवं संतुलित जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया।

इस अवसर पर अधिकारियों के साथ भावनगर मंडल के लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, गुड्स गार्ड सहित बड़ी संख्या में महिला व पुरूष कर्मचारी मौजूद रहे।

उत्तर रेलवे के कठुआ-माधोपुर पंजाब सेक्शन भारी बारिश के कारण रेल यातायात प्रभावित

उत्तर रेलवे के कठुआ–माधोपुर पंजाब सेक्शन में डाउन लाइन पर ब्रिज संख्या 17 पर भारी बारिश के चलते मिसअलाइमेंट होने के कारण रेल यातायात स्थगित किया गया है। जिसके कारण अहमदाबाद मण्डल से चलने/गुजरने वाली कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेगी। जिसका विवरण निम्नानुसार है:

निरस्त ट्रेनें:–

1. दिनांक 30.08.2025 की ट्रेन संख्या 19223 साबरमती–जम्मू तवी एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

2. दिनांक 30.08.2025 की ट्रेन संख्या 19027 बांद्रा टर्मिनस–जम्मू तवी एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

3. दिनांक 30.08.2025 की ट्रेन संख्या 12473 गांधीधाम–श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

4. दिनांक 30.08.2025 की ट्रेन संख्या 19224 जम्मू तवी–साबरमती एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

ट्रेनों के ठहराव, समय और संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

पूजा स्पेशल ट्रेनों से सफर होगा आसान, 2024 अतिरिक्त ट्रिप्स की अधिसूचना जारी

त्योहारों का मौसम शुरू होते ही रेल यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जाती है। इसी बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रेल ने यात्रियों की सुविधा के लिए हजारों विशेष ट्रेन सेवाओं के संचालन का फैसला लिया है। बिहार जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए ही 12000 से अधिक ट्रेनों को चलाने की योजना बनाई जा चुकी है। जिन ट्रेनों के संचालन की योजना बन चुकी है उनका नोटिफिकेशन भी अब जारी किया जाना प्रारंभ हो चुका है । 21 सितंबर से 30 नवंबर 2025 तक कुल 150 पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है जिनके माध्यम से कुल 2024 अतिरिक्त फेरे (ट्रिप्स) सुनिश्चित किए जाएंगे।

भारतीय रेल द्वारा यह निर्णय त्योहारों के अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों से यात्रियों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने और उन्हें अपने प्रियजनों के साथ उत्सव मनाने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। विशेष रूप से उत्तर भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के बड़े स्टेशनों से चलने वाली इन ट्रेनों से महानगरों और ग्रामीण इलाकों के बीच बेहतर संपर्क सुनिश्चित किया गया है।

पूजा स्पेशल इन ट्रेनों की श्रृंखला के तहत दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा सर्वाधिक 48 ट्रेनें चलाई जाएंगी, जो 684 ट्रिप्स पूरा करेंगी। इन ट्रेनों का संचालन मुख्यतः हैदराबाद, सिकंदराबाद और विजयवाड़ा जैसे प्रमुख स्टेशनों से किया जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे ने 14 ट्रेनें अधिसूचित की हैं, जो पटना, गया, दरभंगा और मुजफ़्फरपुर जैसे बिहार के प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेंगी और कुल 588 ट्रिप्स लगाएंगी। पूर्व रेलवे द्वारा कोलकाता, सियालदह, हावड़ा जैसे भीड़भाड़ वाले स्टेशनों से 24 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनके मदद से 198 ट्रिप्स संचालित होंगी।

वहीं पश्चिम रेलवे ने मुंबई, सूरत, वडोदरा जैसे शहरों से 24 स्पेशल ट्रेनें घोषित की हैं जो 204 ट्रिप्स पूरी करेंगी। दक्षिण रेलवे द्वारा चेन्नै, कोयंबत्तूर, मदुरै जैसे स्टेशनों से 10 ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनसे 66 ट्रिप्स होंगी। इसके अलावा पूर्व तट रेलवे से भुवनेश्वर, पुरी और सम्बलपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे से रांची, टाटानगर, उत्तर मध्य रेलवे से प्रयागराज, कानपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से बिलासपुर, रायपुर और पश्चिम मध्य रेलवे से भोपाल, कोटा जैसे स्टेशनों को जोड़ते हुए विशेष ट्रेनें संचालित की जाएंगी।

स्पेशल ट्रेनों की सूची, समय सारणी, रूट और ठहराव की विस्तृत जानकारी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, कफ्ळ्ळउ और नजदीकी रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध है। रेलवे यात्रियों से अपील करता है कि वे इन विशेष ट्रेनों में यात्रा करने के लिए अग्रिम बुकिंग कराएं और अपने टिकट की पुष्टि सुनिश्चित करें। साथ ही यात्रियों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि सफर के दौरान रेल मंत्रालय द्वारा जारी सुरक्षा और स्वच्छता से संबंधित दिशा–निर्देशों का पालन करें।

पश्चिम रेलवे चलाएगी वडोदरा - कोलकाता के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन

यात्रियों की सुविधा हेतु तथा दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ पूजा के अवसर पर बढ़ती हुई यात्रा की मांग को ध्यान में रखते हुए, पश्चिम रेलवे द्वारा वडोदरा – कोलकाता के बीच विशेष किराये पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा।

ट्रेनों का विवरण इस प्रकार है:

1. ट्रेन संख्या 03110/03109 वडोदरा – कोलकाता साप्ताहिक स्पेशल [18 फेरे]

ट्रेन संख्या 03110 वडोदरा – कोलकाता स्पेशल प्रत्येक गुरुवार को वडोदरा से 16:45 बजे प्रस्थान करेगी और शनिवार को 04:05 बजे कोलकाता पहुँचेगी। यह ट्रेन 2 अक्टूबर से 27 नवम्बर, 2025 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 03109 कोलकाता – वडोदरा स्पेशल प्रत्येक मंगलवार को कोलकाता से 08:00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 19:45 बजे वडोदरा पहुँचेगी। यह ट्रेन 30 सितम्बर से 25 नवम्बर, 2025 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में गोधरा, रतलाम, कोटा, गंगापुर सिटी, इदगाह आगरा, टुंडला, गोविंदपुरी, प्रयागराज, पं. दीनदयाल उपाध्याय, सासाराम, गया, तिलैया, नवादा, शेखपुरा, किऊल, झाझा, जसीडीह, मधुपुर, चित्तरंजन, आसनसोल, दुर्गापुर तथा बर्द्धमान स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में एसी–3 टियर, स्लीपर क्लास एवं द्वितीय श्रेणी के सामान्य डिब्बे होंगे।

ट्रेन संख्या 03110 की बुकिंग 30 अगस्त, 2025 से पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, समय और संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बन रहे होल्डिंग एरिया को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए

त्योहारों के दौरान बेहतर भीड़ प्रबंधन के लिए बनाए जा रहे हैं ये होल्डिंग एरिया

नई दिल्ली, (जीएनएस)। आज माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव एक कार्यक्रम में शामिल होने नई दिल्ली स्टेशन पहुँचे। इस दौरान उन्होंने स्टेशन परिसर में बन रहे होल्डिंग एरिया का जायजा लिया और वहाँ मौजूद अधिकारियों को होल्डिंग एरिया का काम जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।

त्योहारों के दौरान, जब यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है, यात्रियों के सुचारू प्रबंधन के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर के अजमेरी गेट की ओर एक स्थायी होल्डिंग एरिया बनाया जा रहा है। होल्डिंग एरिया को तीन कार्यात्मक क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा

प्री–टिकटिंग एरिया: 1950 वर्ग मीटर – इस जगह पर व्यस्त समय में लगभग 2700 यात्री बैठ सकते हैं।

टिकटिंग एरिया: 2288 वर्ग मीटर: इसमें यात्रियों की सुचारू आवाजाही के लिए 3100 यात्री बैठ सकते हैं।

टिकट–पश्चात क्षेत्र: 1570 वर्ग मीटर: इसमें लगभग 1350 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है, जिससे कतार में लगने, सुरक्षा जाँच और सामान की स्कैनिंग के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध है।

इस समर्पित होल्डिंग क्षेत्र में यात्रियों के लिए निम्नलिखित सुविधाएँ उपलब्ध होंगी:

- 22 टिकट काउंटर
- 2 शौचालय ब्लॉक
- जन संबोधन प्रणाली
- सूचना के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड
- ए आई आधारित निगरानी कैमरे
- सामान स्कैनर
- यात्रियों के मार्गदर्शन के लिए साइनेज
- मेट्रो कनेक्टिविटी से एकीकृत

वर्तमान में, इस होल्डिंग क्षेत्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस होल्डिंग क्षेत्र के निर्माण के दौरान, एटीएम काउंटरों को स्थानांतरित करना, दो इलेक्ट्रिक हाईमास्ट को स्थानांतरित करना, दो मोबाइल टावरों को हटाना, प्रीपेड टैक्सी स्टैंड को स्थानांतरित करना, दिल्ली पुलिस केबिन को स्थानांतरित करना जैसे कई चुनौतीपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं।

असारवा और कानपुर सेंट्रल के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का संचालन

रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए असारवा और कानपुर सेंट्रल के बीच विशेष किराये पर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:

ट्रेन संख्या 01906/01905 असारवा–कानपुर सेंट्रल–असारवा साप्ताहिक स्पेशल (14 फेरे)

ट्रेन संख्या 01906 असारवा–कानपुर सेंट्रल स्पेशल 23 सितंबर 2025 से 04 नवंबर 2025 तक असारवा से प्रति मंगलवार 09.15 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 07.00 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी। इस तरह ट्रेन संख्या 01905 कानपुर सेंट्रल–असारवा स्पेशल 22 सितंबर 2025 से 03 नवंबर 2025 तक कानपुर सेंट्रल से प्रति सोमवार 08.15 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 05.45 बजे असारवा पहुंचेगी।

मार्ग में दोनों दिशाओं में यह ट्रेन हिम्मतनगर, डूंगरपुर, जावर, उदयपुर सिटी, मावली, चंदेरिया, मांडल गढ़, बूंदी, केशोराय पाटन, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, बयाना और फतेहपुर सीकरी, ईदगाह, टूंडला, फिरोजाबाद तथा इटावा स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी 2–टियर, एसी 3–टियर, स्लीपर एवं सामान्य श्रेणी के कोच रहेंगे।

ट्रेन संख्या 01906 की बुकिंग 30 अगस्त 2025 से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, समय और संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

सरकार ने लाइव इवेंट और कॉन्सर्ट अर्थव्यवस्था पर वार्ता शुरू की, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने नई दिल्ली में संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की पहली बैठक की अध्यक्षता की

(जीएनएस)।

लाइव इवेंट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की पहली बैठक 26 अगस्त को राष्ट्रीय मीडिया केंद्र, नई दिल्ली में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

अपने हाल के संबोधनों में, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के लाइव मनोरंजन क्षेत्र की विशाल अप्रयुक्त क्षमता पर प्रकाश डाला और रोजगार, निवेश, पर्यटन और भारत के सांस्कृतिक एवं वैश्विक प्रभाव के प्रमुख प्रेरक के रूप में इसकी भूमिका पर जोर दिया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के निर्देशन में जुलाई 2025 में गठित, संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) भारत की कॉन्सर्ट अर्थव्यवस्था को आकार देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों, उद्योग संघों, संगीत

अधिकार समितियों और प्रमुख इवेंट कंपनियों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाता है।

बैठक में सूचना एवं प्रसारण, संस्कृति, युवा कार्यक्रम एवं खेल, कौशल विकास एवं उद्यमिता, वित्त मंत्रालय, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) और भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रमुख प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक में महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्य सरकारों के अधिकारी भी उपस्थित थे।

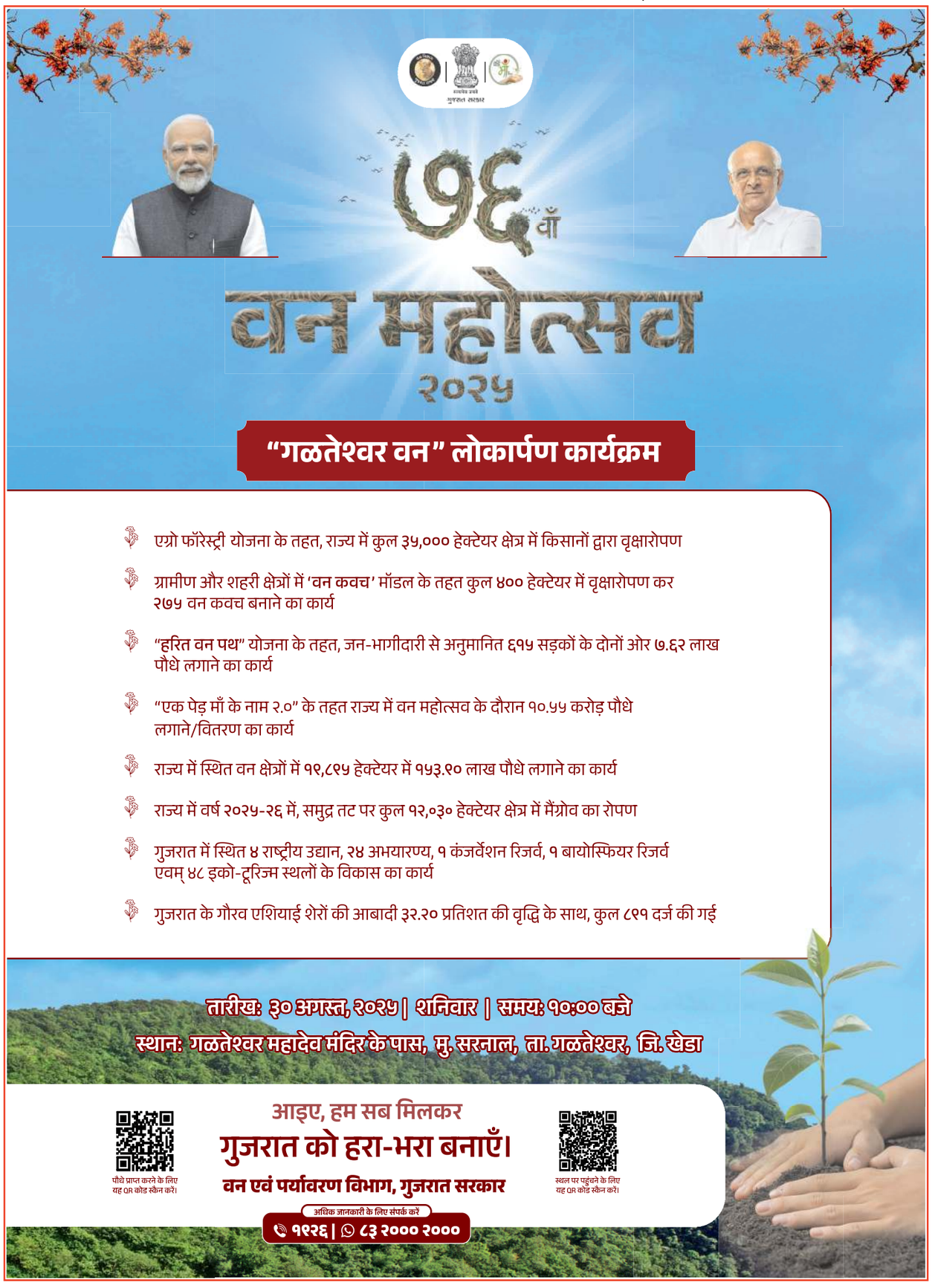

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य स्तरीय स्वागत ऑनलाइन जनशिकायत निवारण कार्यक्रम में जिला स्तर पर आपसी समन्वय के जरिए नागरिकों की समस्याओं के सकारात्मक निराकरण के निर्देश दिए

गांधीनगर, 29अगस्त : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को अगस्त महीने के राज्य स्तरीय स्वागत ऑनलाइन जनशिकायत निवारण कार्यक्रम में जिला स्तर पर परस्पर समन्वय बनाकर लोगों की समस्याओं का सकारात्मक निराकरण करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने अगस्त-25 के राज्य स्तरीय ह्यस्वागतह्न ऑनलाइन जनशिकायत निवारण कार्यक्रम में उनके समक्ष प्रस्तुत की गईं 12 समस्याओं को सुना। इनमें से एक किसान की समस्या को सुनने के बाद उन्होंने यदा-कदा नर्मदा नहर छलकने के कारण उस किसान के खेत में होने वाले नुकसान का स्थायी समाधान ढूंढ़ने और सरदार सरोवर नर्मदा निगम को उस किसान को नुकसान का मुआवजा देने के स्पष्ट निर्देश दिए।

उल्लेखनीय है कि राज्य स्तरीय ह्यस्वागतह्न (स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रिवेंसेस बाई एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी) कार्यक्रम में आमजन अपनी अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इसके अंतर्गत अगस्त-25 के राज्य स्तरीय ह्यस्वागतह्न में कुल 170 अभ्यावेदक अपनी विभिन्न समस्याओं के साथ उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री कार्यालय की जनसंपर्क इकाई ने इनमें से लगभग 160 समस्याओं को सुनने के बाद उन्हें संबंधित जिला प्रशासन एवं सरकार के विभागों को उचित कार्रवाई के निर्देश के साथ भेज दिया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के समक्ष प्रस्तुत की गईं 12 समस्याओं को उन्होंने ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने गुजरात हाउसिंग बोर्ड द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को दिए जाने वाले आवासों के दस्तावेजों के कामकाज में तेजी लाने और आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने के हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त को निर्देश दिया।

बनासकांठा जिले के सामान्य और छोटे वर्ग के 450 से अधिक लोगों ने दस्तावेज के साथ खरीदी गई गैर-कृषि भूमि का कब्जा प्राप्त करने में लंबे समय से आ रही मुश्किल के बारे में राज्य स्तरीय ह्यस्वागतह्न में मुख्यमंत्री के समक्ष अभ्यावेदन दिया। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर को त्वरित कार्रवाई करते हुए भूमि हड़पने की इस शिकायत पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

भारत की राष्ट्रपति ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) को स्कोप एमिनेंस पुरस्कार प्रदान किए

(जीएनएस)।

भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज नई दिल्ली में स्कोप एमिनेंस पुरस्कार प्रदान किए। यह कार्यक्रम वित्त मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के सहयोग से लोक उद्यम स्थायी सम्मेलन (स्कोप) की ओर से आयोजित किया गया था और इसमें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी, लोक उद्यम विभाग सचिव श्री के. मोसेस चालई, स्कोप अध्यक्ष श्री के. पी. महादेवस्वामी और स्कोप महानिदेशक श्री अतुल सोबती भी मौजूद थे।

कार्यक्रम में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) के शीर्ष नेतृत्व और एससीओपीई के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साझेदार संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

इस अवसर पर बोलते हुए, अध्यक्ष श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि स्कोप एमिनेंस पुरस्कार भारत के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव हैं। सार्वजनिक क्षेत्र और उसके नेतृत्वकताओं की सराहना

करते हुए, उन्होंने कहा कि वे सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, तकनीकी और नैतिक सहित सभी मानदंडों पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने महिला सशक्तिकरण, संपोषित विकास, कॉरपोरेट प्रशासन, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और नवाचार जैसे विविध आयामों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को सम्मानित करने के लिए स्कोप की सराहना की।

राष्ट्रपति ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र आर्थिक विकास और सामाजिक समावेशन का एक सशक्त माध्यम रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

आत्मनिर्भर भारत और ह्यमेक इन इंडियाह्न अभियानों में सीपीएसई की प्रभावी भूमिका की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली - आकाशतीर ने अपनी अचूक क्षमता का प्रदर्शन किया।

अपने संबोधन में, श्री पंकज चौधरी ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र ने अपनी स्थापना के बाद से एक लंबा सफर तय किया है और राष्ट्र निर्माण में एक रणनीतिक भूमिका निभाई है। उन्होंने इस विषय पर जोर दिया कि अनिश्चितता और संकट के दौर में भी, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का प्रदर्शन लगातार बना रहा है और वे हमेशा विकास की राह पर हैं।

इस अवसर पर अपने संबोधन में, श्री के. मोसेस चालई ने कहा कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) ने देश के विकास और सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उन्होंने कहा कि लगभग 15 लाख लोगों को सीधे रोजगार प्रदान करते हुए और अप्रत्यक्ष रूप से देश भर में लाखों लोगों की आजीविका को सहारा देते हुए, सार्वजनिक क्षेत्र राष्ट्र निर्माण और आर्थिक विकास की दोहरी जिम्मेदारी निभाता है।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मैसूर में सुत्तूर मठ में आयोजित समारोह में शामिल हुए

(जीएनएस)।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज कर्नाटक के मैसूर स्थित श्री सुत्तूर मठ में आयोजित समारोह में शामिल हुए। समारोह का आयोजन डॉ. शिवरात्रि राजेंद्र महास्वामी जी की 110वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में किया गया था। इस अवसर पर उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा ही असली पूजा है। श्री शिवराज सिंह ने कहा कि राजनीति तोड़ती है, लेकिन धर्म जोड़ता है, आज धर्म ने हम सभी को पीड़ित मानवता की सेवा के लिए जोड़ दिया हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में विभिन्न राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि, संत-महात्मा, भक्तगण उपस्थित रहे।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मठ वर्षों से सामाजिक कल्याण और मानवता की दिशा में अतुलनीय भूमिका का निर्वहन करता आ रहा है। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक विभिन्न क्षेत्रों में मठ के कार्य संचालन से बदलाव की दिशा तय हुई है। जिस समर्पण और सेवाभाव के साथ काम किया जा रहा है, वह यहां के वातावरण को अद्वितिय बनाता है। उन्होंने कहा कि राजनीति तोड़ती है, धर्म जोड़ता है और पीड़ित मानवता की सेवा ही असली पूजा है। आगे उन्होंने कहा कि उचित धर्म के पालन के साथ मठ सेवाकार्य में जुटा है और मैं भी अंतरात्मा से कोशिश करता हूं कि लोगों की अधिक से अधिक सेवा कर सकूं।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मुझे कृषि मंत्री बनने का सौभाग्य दिया। बतौर कृषि मंत्री मैं यह मानता हूं कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा, किसान प्राण हैं, अन्नदाता हैं, जीवनदाता हैं और किसानों की सेवा ही मेरे लिए असली आराधना है।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने कहा कि हम किसान भाई-बहनों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास में जुटे हैं।

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) की प्रगति एवं अगले चरण पर मंथन संबंधी सम्मेलन

प्रगति का आकलन करने और आगे की राह की योजना बनाने के लिए एक मंच

(जीएनएस)।

पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, 1 सितंबर, 2025 को भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) प्रगति एवं एसबीएम-जी के अगले चरण पर मंथन संबंधी एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित करेगा।

विचार-विमर्श की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सीआर पाटिल, राज्य मंत्री श्री वी सोमन्ना, पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव श्री अशोक केके मीणा और अपर सचिव एवं प्रबंध निदेशक एनजेजेएम और एसबीएम (जी), श्री कमल किशोर सोन करेंगे। यह पूरे दिन चलने वाला कार्यक्रम देश भर से वरिष्ठ नेतृत्व एकत्रित करेगा, जिसमें ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी 17 राज्य मंत्री, 21 अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव और 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 26 मिशन निदेशक शामिल होंगे।

सम्मेलन में स्वच्छ भारत मिशन (जी) के अंतर्गत उपलब्धियों और प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इसका मुख्य फोकस खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) प्लस मॉडल की स्थिरता, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को सुदृढ़ करना और गोबरधन तथा मल अपशिष्ट प्रबंधन जैसे नवाचारी मॉडलों का विस्तार करना होगा। एक ओपन हाउस सत्र मंथन के लिए मंच तैयार करेगा, जिसमें अगले चरण की प्राथमिकताओं की रूपरेखा तय की जाएगी। इसमें विशेष बल प्रणाली सुदृढ़ीकरण, डिजिटल नवाचार और जलवायु प्रतिस्कंदन संबंधी लक्ष्यों के साथ तालमेल पर होगा।

अब तक स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम-जी) चरण दो के अंतर्गत 11.93 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत शौचालय, 2.62 लाख सामुदायिक स्वच्छता परिसर, 4.76 लाख खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) प्लस मॉडल गांव, 950 से अधिक चालू गोबरधन परियोजनाएं और 124 मल-अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित किए गए हैं। चूंकि एसबीएम-जी चरण2 मार्च 2026 में अपने समापन के करीब है, यह सम्मेलन लाभों को समेकित करने, सीखे गए सबक पर विचार करने और एसबीएम-जी के अगले चरण के लिए एक मजबूत रोडमैप तैयार करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

पेयजल और स्वच्छता विभाग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी की उम्मीद करता है, जिनकी अंतर्दृष्टि और अनुभव एसबीएम-जी के अगले चरण की रूपरेखा को आकार देने में महत्वपूर्ण होंगे, जिससे स्वच्छ, सुजल और सतत गांवों के राष्ट्रीय विजन को आगे बढ़ाया जा सकेगा।

आईएनसीओआईएस और एनडीएमए ने चेन्नई में भारतीय तटरेखा के लिए समुद्री बहु-खतरनाक सेवाओं पर एक सम्मेलन का आयोजन किया

(जीएनएस)।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार के भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (आईएनसीओआईएस) ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के सहयोग से 29 अगस्त 2025 को चेन्नई में भारतीय तटरेखा के लिए समुद्री बहु-खतरनाक सेवाओं पर एक सम्मेलन का आयोजन किया।

इस सम्मेलन का उद्घाटन एनडीएमए के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) ने किया। उन्होंने कहा कि मछुआरा समुदाय को किसी भी चक्रवात से सुरक्षित रखने में मदद के लिए सेल प्रसारण के माध्यम से एक नई सामान्य चेतावनी प्रणाली 1 सितंबर से परीक्षण के आधार पर शुरू की जाएगी।

एनडीएमए के सदस्य श्री हसनैन ने कहा कि मोबाइल प्रसारण एप्लिकेशन में उन्नत तकनीक होगी, जहां मोबाइल साइलेंट मोड में होने पर भी, यह एक ध्वनि उत्पन्न करेगा जो मछुआरों और ऐप धारकों को किसी भी प्राकृतिक आपदा या चक्रवात के

बारे में सचेत करेगा। उन्होंने 2023 में गुजरात तट पर आए चक्रवात बिपरजॉय से कुशलतापूर्वक निपटने का उदाहरण दिया, जहाँ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) सहित कई हितधारकों ने मिलकर निचले इलाकों में फंसे लोगों को निकाला और 3.2 करोड़ से ज्यादा अलर्ट संदेश भेजकर जान-माल की हानि को रोकने में मदद की। उन्होंने जनता से विभिन्न मौसम संबंधी चेतावनियाँ प्राप्त करने के लिए एनडीएमए का सचेत ऐप या आईएनसीओआईएस का समुद्र ऐप डाउनलोड करने का आग्रह किया।

लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने कहा, "आईएनसीओआईएस न केवल भारत के तटों की सुरक्षा में, बल्कि आपदा कूटनीति को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बहु-संकट की तैयारी लचीलेपन का आधार है, जिसके लिए विज्ञान, शासन, सशस्त्र बलों और समुदायों द्वारा समान रूप से संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता है।"

प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए, आईएनसीओआईएस के निदेशक डॉ. टी.एम. बालकृष्णन नायर ने अपने 'विज्ञान से समाज' के दृष्टिकोण पर जोर दिया और सुनामी के लिए शून्य झूठे अलार्म के केंद्र के रिकॉर्ड की पुष्टि की, जिससे अनावश्यक निकासी से बचने में मदद मिली है और साथ ही पूर्व चेतावनियों में जनता का विश्वास भी बना रहा है। स्वागत समारोह में कहा गया, 'तैयारी सुरक्षा का सबसे मजबूत तरीका है' और आपदा प्रबंधकों, समुद्री एजेंसियों, उद्योग और समुदायों के बीच गहरी साझेदारी का आह्वान किया गया।

डॉ. बाला ने जोर देकर कहा कि "हमारा दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करना है कि भारत के तट पर हर जीवन और आजीविका विज्ञान-संचालित पूर्व चेतावनी सेवाओं के माध्यम से सुरक्षित रहे। समुद्री बहु-खतरों के विरुद्ध तैयारी वैकल्पिक नहीं है; यह लचीलेपन के लिए आवश्यक है।"

राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईओटी) के निदेशक प्रो. बालाजी रामकृष्णन ने कहा कि सुनामी और चक्रवात की चेतावनियों के प्रसार में एमएसएसआरएफ सहित सभी संस्थानों के समन्वित प्रयासों से तटीय समुदाय को सुरक्षित रहने में मदद मिली है। श्री बालाजी ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मिशन मौसम के बारे में बात की, जिसके लिए देश को किसी भी मौसम संबंधी चुनौतियों के लिए तैयार करने हेतु 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

केंद्रीय गृह सचिव ने बीपीआरएंडडी के 55वें स्थापना दिवस पर 'नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयनः पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी और विश्वास' विषय पर डॉ. आनंद स्वरूप गुप्ता स्मारक व्याख्यान दिया

(जीएनएस)।

केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन ने आज नई दिल्ली में मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी) के 55 वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह सचिव ने 'नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयनः पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी और विश्वास' विषय पर डॉ आनंद स्वरूप गुप्ता स्मारक व्याख्यान दिया। केंद्रीय गृह सचिव ने बीपीआर एंड डी के प्रकाशनों अर्थात् राष्ट्रीय पुलिस अनुसंधान भंडार-खंड क्कक भारत में जेल अधिकारियों की निर्देशिका - 2025, और परियोजनाओं का संग्रह - खंड श्कक श्कक और क (विभिन्न सूक्ष्म मिशनों, 2021-2025 के अंतर्गत पूरी की गई 15 परियोजनाएं) भी जारी किए। उन्होंने विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और वर्ष 2024 और 2025 के लिए सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक प्राप्तकताओं को भी सम्मानित किया।

केंद्रीय गृह सचिव ने डॉ. आनंद स्वरूप गुप्ता स्मृति व्याख्यान देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की स्मार्ट पुलिसिंग परिकल्पना के अनुरूप और केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में, बीपीआर एंड डी भारत के पुलिस बलों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बीपीआरएंडडी की उभरती भूमिका के तीन महत्वपूर्ण आयामोंः जटिल पुलिस चुनौतियों का समाधान करने वाले एक मजबूत थिंक टैंक के रूप में इसका उदय; सीडीटीआई और सीएपीटी के माध्यम से प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में इसका नेतृत्व; और नीति तथ व्यवहार के बीच की खाई को पाटने के लिए राज्यों तक इसकी पहुंच, विशेष रूप से नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की निगरानी का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन सुधारों की बीपीआरएंडडी की करीबी निगरानी कानून प्रवर्तन में इसकी परिवर्तनकारी भूमिका को दर्शाती है। अपने समापन भाषण में उन्होंने इस बात पर बल दिया कि बीपीआर एंड डी खुद को विचारक संगठन में बदलकर पुलिस सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

इससे पहले बीपीआर एंड डी के महानिदेशक श्री आलोक रंजन ने अपने स्वागत भाषण में अनुसंधान, पुलिस सुधार, क्षमता निर्माण और आधुनिकीकरण के लिए विचारक के रूप में ब्यूरो की साढ़े पांच दशक की सेवा पर प्रकाश डाला।

भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के अंतर्गत संयुक्त ऋण तंत्र (जेसीएम) पर सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

(जीएनएस)।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के अंतर्गत संयुक्त ऋण व्यवस्था (जेसीएम) पर जापान सरकार के साथ एक सहयोग ज्ञापन (एमओसी) पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे जलवायु कार्रवाई के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता का पता चलता है और यह पेरिस समझौते के कार्यान्वयन में एक और मील का पत्थर है।

इस महीने की शुरूआत में हस्ताक्षरित एमओसी भारत-जापान सहयोग के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र - 'बेहतर भविष्य के लिए हरित ऊर्जा फोकस' का हिस्सा है - जिस पर आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी जापान यात्रा के दौरान प्रकाश डाला।

भारत और जापान के बीच आर्थिक, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक सहयोग का एक मजबूत इतिहास रहा है। वर्तमान सहयोग ज्ञापन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन शमन पर भारत और जापान के बीच साझेदारी को मजबूत करना है। पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय नामित

एजेंसी (एनडीएआईएपीए) द्वारा अनुच्छेद 6.2 के अंतर्गत अनुमोदित निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकियाँ, 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने हेतु भारत की दीर्घकालिक निम्न-कार्बन विकास रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक हैं।

वर्तमान में, यह रणनीति बहुत खचीर्ली है और इसके लिए व्यवहार्यता अंतर निधि की आवश्यकता है। संयुक्त आयोग (जेसीएम) इन कम कार्बन प्रौद्योगिकियों से संबंधित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निवेश प्रवाह, प्रौद्योगिकी सहायता, जिसमें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण समर्थन शामिल है, को प्रोत्साहित करेगा। यह निम्न कार्बन प्रौद्योगिकियों और उपकरणों, मशीनरी, उत्पादों, प्रणालियों और बुनियादी ढाँचे से संबंधित उच्च प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों को स्थानीयकृत करने के लिए घरेलू पारिस्थितिकी तंत्र और साझेदारियाँ भी विकसित करेगा, जिससे उनके बड़े पैमाने पर उपयोग का मार्ग प्रशस्त होगा।

यह सहयोग ज्ञापन भारत में ग्रीनहाउस गैसों (जीएचजी) में कमी या निष्कासन तथा सतत विकास में योगदान देने वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन को और सुगम बनाएगा। यह पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के अंतर्गत ऐसी परियोजनाओं से उत्पन्न कार्बन क्रेडिट का जापान और इसी तर्ज पर अन्य देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी संभव बनाएगा, जिससे भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) प्रतिबद्धताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को केंद्रीय मंत्रिमंडल से कार्यान्वयन नियमों (आरओआई) को अंतिम रूप देने और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विदेश मंत्रालय (एमईए) के परामर्श से पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के तहत इसी तर्ज पर अन्य देशों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए अनुमोदन भी प्राप्त हुआ है।